JAMMU JAGRAN CITY 05-03-2011

नहीं बचा था जहां पर वाहनों की कतार न हिल पाना भी असंभव था। वहां तवी पुल निकलने में इसके बाद भी घंटा लग गए। लिए रवाना होने के साथ ही सुरक्षा बलों सदस्यों की भी विशेष टीमें बनाई गई थीं। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने जा रहे आत

कोई बेहतर तो किसी ने दिखावा बताया

खुशखबरी

- कश्मीरी पंडितों के लिए खुला जगटी टाउनशिप का दरवाजा

जम्मू: विस्थापित कैंपों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए शुक्रवार को जगटी टाउनशिप का दरवाजा खुल गया। दो कमरों के फ्लैट्स को कुछ ने बदहाल जीवन जी रहे पंडितों के लिए बेहतरी का सबब माना है तो कुछ ने इसे एक बार फिर विस्थापन की प्रक्रिया करार दिया है।

ऑल पार्टीज माइग्रेंटस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि 15 जुलाई 2007 को उन्होंने सरकार को ज्ञापन देकर वादी में तीन सेटेलाइट टाउनशिप बनाने की मांग की थी, जहां कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाया जाता। घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के मंदिरों व धार्मिक स्थलों की देखरेख व बेरोजगार युवाओं के लिए दस हजार नौकरियों की मांग के साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। जगटी में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान संगठन के महासचिव अरूण कांदरू व सचिव रविंद्र पंडिता ने कहा कि सरकार द्वारा कैंपों में रहने वाले पंडितों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है, लेकिन उनकी मांगों पर गौर करने से सरकार पंडितों के लिए और भी बेहतर कदम उठा सकती थी। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कांफ्रेंस के महासचिव हीरा लाल चट्टा ने कहा है कि केंद्र की ओर से जगटी में पंडितों के लिए बनाए गए आशियाने महज एक दिखावा है। यह मात्र मुख्यमंत्री को खुश करने का एक माध्यम है। चट्टा ने सरकार पर पंडितों को जम्मू से दूर बसाने और पंडित व डोगरा समुदाय के बीच बढ़ते मैत्री के रिश्तों में दरार डालने का आरोप लगाया है।

अपील : प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर भल्ला ने उठाया रिफ्यूजियों के पुनर्वास का मुद्दा

विस्थापितों के लिए 18 अरब की दरकार

जम्मू, जागरण ब्यूरो : वर्ष 1947, 1965 व 1971 के रिफ्यूजियों के स्थायी पुनर्वास के लिए राज्य को केंद्र सरकार से लगभग 18 अरब रुपये के पैकेज की जरूरत है। केंद्र से पैकेज मिलने की उम्मीद लेकर राजस्व मंत्री ने पुनर्वास संबंधी ज्ञापन शुक्रवार को जम्मू दौरे पर आए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सौंपा।

रिफ्यूजियों की मुश्किलों का जायजा लेने के लिए ज्ञापन में भल्ला गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के गठन पर भी जोर दिया। वर्ष 1998 में गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के लिए भी केंद्र ने ऐसी ही कमेटी का गठन किया था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1947 में विस्थापित हुए गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के स्थायी पुनर्वास के लिए 700 करोड़ चाहिए। गुलाम कश्मीर से विस्थापित हुए 31,619 परिवारों में से 26319 परिवार राज्य में बस गए थे। इनमें से 22719 गांवों में बस गए थे। इनमें से 8409 परिवारों को पूरी जमीन नहीं मिली।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपते राजस्व मंत्री रमण भल्ला। जागरण

रिफ्यूजियों का कहना है कि स्थायी पुनर्वास के लिए हर परिवार को तीन लाख के हिसाब से पंद्रह लाख मिलना चाहिए। यह राशि 700 करोड़ बनती है। पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के स्थायी पुनर्वास के लिए 750 करोड़ व व 1965 के छंब रिफ्यूजियों के स्थायी पुनर्वास के लिए अभी 225 करोड़ की जरूरत है। केंद्र से मिली सहायता में से 1198 परिवारों को 2,99,50000 रुपये दिए जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 1971 के छंब रिफ्यूजियों के 4600 परिवारों में 699 को पूरी जमीन नहीं मिली है। इन परिवारों को अब तक 3,0500000 रुपये दिए जा चुके हैं। अगर उन्हें स्थायी पुनर्वास के लिए पंद्रह लाख देने के लिए सौ करोड़ की जरूरत पड़ेगी।

27 फीसदी आरक्षण की मांग

जम्मू : जम्मू-कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी महासभा के सदस्यों का एक शिष्टमंडल प्रधान बोधराज भगत व महासचिव मदनलाल चलोत्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री से मिला और मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। पत्र में जम्मू कश्मीर में ओबीसी के आरक्षण को दो फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग की गई है। शिष्टमंडल में स. दर्शन सिंह आजाद, राज कपूर, शाम लाल गांधी, राज कुमार चौधरी व महेश्वर विश्वकर्मा शामिल थे।

जम्मू को विशेष वित्तीय पैकेज देने की मांग : जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जम्मू के विकास तथा इससे हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की है। मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने पत्रकारवार्ता कर डिलिमिटेशन कमीशन के मुद्दे पर राउंड टेबल कांफ्रेंस बुलाने की भी मांग की।